



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

6 JUL 1971
Tah
GOVT. OF INDIA

सं० 66] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 30, 1971/बैशाख 10, 1893

No. 66] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 30, 1971/VAISAKHA 10, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 30th April 1971

SUBJECT.—Import policy for registered exporters for the period April 1971—March 1972. (Amendment No. 1).

No. 46-ITC(PN)/71.—Attention is invited to the import policy for registered exporters contained in the Import Trade Control Policy Book Vol. II for the period April 1971—March 1972 issued under the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 44 ITC(PN)/71, dated 30th April, 1971.

2. Under para 39(ii) of Part B of Section I of the aforesaid Policy Book, provisions regarding endorsement of items on replenishment licences on the basis of an actual user licence have been laid down. On a review of the matter it has been decided that for the purpose of operation of the said para, the release orders for raw materials and components issued on or after 1st April, 1971 under the A. U. policy to the same industrial unit would also be equated with the A. U. licence, except in the case of certain specified items. The item applied for on the basis of such release orders will, however, be allowed only through release orders on the canalising agency and no direct import thereof will be permitted.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1971

विषय.—अप्रैल 1971—मार्च, 1972 अवधि के लिये पंजीकृत निर्यातकों के लिये आयात नीति (संशोधन संख्या 1)

संख्या 46-आई० टी० सी० (पी० एन०)/71.—विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 44-आई० टी० सी० (पी० एन०)/71 दिनांक 30-4-1971 के अन्तर्गत अप्रैल, 1971-मार्च, 1972 अवधि के लिये जारी की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक के बाल्यूम-2 में निहित पंजीकृत निर्यातकों के लिये आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

उपर्युक्त नीति पुस्तक के खंड ए के भाग बी की कांडिका 39 (2) में, वास्तविक उप-भोक्ता लाइसेंस के आधार पर प्रतिपूर्ति लाइसेंसों पर मदों के पृष्ठांकन करने के सम्बन्ध में व्यवस्थायें निर्धारित कर दी गई हैं।

मामले की पुनरीक्षा कर यह निश्चय किया गया है कि उक्त कांडिका को प्रभावी करने के उद्देश्य से वास्तविक उपभोक्ता नीति के अन्तर्गत 1-4-71 को अथवा उसके पश्चात् उसी औद्योगिक एकक को कच्चे माल तथा संघटकों के लिये जारी किए गए बंटन आदेशों को कुछ विशिष्टकृत मदों को छोड़कर अन्य के लिये भी वास्तविक उपभोक्ता लाइसेंस के बराबर समानता दी जाएगी, किन्तु ऐसे बंटन आदेशों के आधार पर आवेदित मदों की स्वीकृति, केवल सरणीबद्ध करने वाले अभिकरण को ही बंटन आदेशों के माध्यम से ही दी जाएगी और उसकी किसी मद के सीधे आयात की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

SUBJECT.—*Import policy for registered exporters for the period April 1971—March 1972—Scheme for grant of import benefits to the eligible Export Houses.*

No. 47-ITC(PN)/71.—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters contained in the Import Trade Control Policy Book for the period April 71—March 72 issued under the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 44-ITC(PN)/71 dated 30th April, 1971.

2. In para 3 of Part C of the Section I of the aforesaid Policy Book, the conditions for grant of eligibility certificates to merchandising Export Houses have been laid down. In modification of para 3(i)(a), it has been decided that requests for grant of eligibility certificates to Export Houses on the basis of exports of non-traditional products, in addition to those listed in para 9 of Part C of Section I of Vol. II would also be considered provided the value of such exports is not less than Rs. 25 lakhs in the year 1969 or 1970 and provided further that the other conditions laid down in para 3 of Part C are satisfied. The Export Houses who are issued eligibility certificates in terms of this decision will be entitled to only the following three benefits provided in the scheme:—

- (1) import replenishment licence against their own exports under the import policy for registered exporters. Such licences will be governed by the conditions laid down in para 19 of Part B and para 13 of Part C of Section I Vol. II of the Import Policy for Registered Exporters;

- (ii) import of goods on behalf of actual users without obtaining letter of authority in favour of the Export House; and
- (iii) organising bulk imports by obtaining in their name the licences for raw materials, components and spares on behalf of actual users who are their clients.

3. Recognised Export Houses satisfying the aforesaid conditions should apply to the Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi on or before 30th June, 1971 or within three months of the issue of certificate of recognition by the Ministry of Foreign Trade, whichever is later, for grant of certificate of eligibility. The applications should be supported by a certificate from any authorised dealer in foreign-exchange or a Chartered Accountant, indicating the full description of the non-traditional products exported and the f.o.b. value of such exports made by them during the calendar year 1969 or 1970, giving separately the value of goods relating to different manufacturers with their particulars.

P. K. SAMAL,
Chief Controller of Imports and Exports.

विषय .—1971-72 अवधि के लिये पंजीकृत निर्यातकों के लिये आयात नीति—उपयुक्त निर्यात सदनों को आयात सम्बन्धी लाभ प्रदान करने के लिये योजना ।
(संशोधन संख्या 2)

संख्या 47—आई० टी० सी० (पी० एन०)/71.—विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 44 आई० टी० सी० (पी० एन०)/71 दिनांक 30-4-1971 के अन्तर्गत जारी की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक के वा०-2 में निहित पंजीकृत निर्यातकों के लिये आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

उपयुक्त नीति पुस्तक के खंड 1 के भाग सी की कंडिका 3 में व्यापारी निर्यात सदनों को उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्रदान करने के सम्बन्ध में नियम निर्धारित किए गए हैं । कंडिका 3 (i) (ए) का संशोधन कर यह निश्चय किया गया है कि वा०-2 के खंड 1 के भाग सी की कंडिका 9 में सूचीबद्ध के अलावा गैर परम्परागत उत्पादों के निर्यात के आधार पर निर्यात सदनों की उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्रदान करने के आवेदनों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते कि 1969 अथवा 1970 वर्ष में ऐसे निर्यात 25 लाख रुपये से कम के नहीं हैं और बशर्ते कि कंडिका 3 में निर्धारित शर्तों का पालन किया जाता है । वे निर्यात सदन जिन्हें प्रस्तुत निर्णय के अनुसार उपयुक्तता प्रमाण-पत्र जारी किए जाते हैं, वे परियोजना में दिए गए लाभ में से निम्नलिखित केवल तीन लाभ प्राप्त करने के अधिकारों होंगे :—

(i) पंजीकृत निर्यातकों के लिये आयात नीति के अन्तर्गत अपने स्वयं के निर्यात के विपरीत आयात आपूर्ति लाइसेंस । ऐसे लाइसेंस पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति के खंड 1, वा०-2 के भाग बी की कंडिका 19 और भाग सी की कंडिका 13 में निर्धारित शर्तों द्वारा शासित होंगे ।

(ii) निर्यात सदन के नाम में प्राधिकार पत्र प्राप्त किए बिना ही वास्तविक उप-योजताओं की ओर से माल के आयात करने के, और

(iii) वास्तविक उपयोगिता का और से जो कि उनके अपने मुआविकल हैं अपने नाम में कच्चे माल के लिये लाइसेंस प्राप्त करने पर भारी मात्रा में आयात की व्यवस्था करने का

वे मान्यताप्राप्त निर्यात सदन जो उपर्युक्त नियमों का पालन करते हैं, उन्हें चाहिये कि वे उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्रदान करने सम्बन्धी आवेदनों को 30 जून, 1971 अथवा इससे पूर्व अथवा विदेश व्यापार मंत्रालय द्वारा मान्यता प्रमाण-पत्र जारी करने की तिथि से तीन मास के भीतर चाहें जो भी बाद में हो, मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात, नई दिल्ली को प्रस्तुत करें। आवेदन पत्रों के साथ आयातित गैर परम्परागत उत्पादों का पूरा विवरण और इस प्रकार के निर्यात जो उनके द्वारा पचास वर्ष 1969-70 के दौरान किया गया है, उसके जहाज पर निःशुल्क मूल्य को संकेतित करते हुये और विभिन्न निर्माणकर्ताओं से सम्बन्धित माल के मूल्य को उनके विवरण के साथ अलग-अलग देते हुये विदेशी मुद्रा देने वाले किसी प्राधिकृत व्यापारी या सनदी लेखापाल से प्राप्त प्रमाण-पत्र को भेजना चाहिये।

पी० के० समाल,
मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात।